जलवायु परिवर्तन के कारकों को कम करने के लिए सामूहिक भागीदारी जरूरी : सचिव

प्रमुख संवाददाता, रांची

राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा असेसिंग वल्नेरेबिलिटी एंड रिस्क : स्ट्रैटेजिक फॉर ए क्लाइमेट रेसिलिएंट झारखंड विषय पर कार्यशाला आयोजित की गयी. इसमें झारखंड की जलवायु सहनशीलता के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गयी. नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने राज्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर विमर्श किया. कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए वन सचिव अबु बकर सिद्दकी ने जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) के अनुसार राज्य में किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया. देश के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में झारखंड की भागीदारी सुनिश्चित करने में योगदान पर चर्चा की. उन्होंने राज्य में

कार्यशाला में उपस्थित वन विभाग के पदाधिकारी व अन्य.

जलवायु परिवर्तन के कारकों को कम करने के लिए सामूहिक और स्थानीय दृष्टिकोण की जरूरत बतायी. कार्यशाला में आइआइटी मंडल, आइआइटी (आइएसएम) धनबाद, नाबार्ड, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बीआइटी मेसरा, जीआइजेड, टीइआरआइ, आइइइएफए, पीडब्ल्यूसी समेत अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व वन बल प्रमुख (पीसीसीएफ एंड एचओएफएफ) सत्यजीत सिंह ने जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए की जा रहीं विभागीय गतिविधियों पर बातें की. कहा : राज्य में बड़े पैमाने पर पौधारोपण, मृदा व जल संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा की पहल जैसे कार्य पूरी गंभीरता और ईमानदारी से किये जा रहे हैं.

मजबूत कार्बन बाजार ढांचा विकसित करने की जरूरत

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ-सीएएमपीए) रवि रंजन ने कहा कि समुदायों और संस्थानों को जलवायु जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सशक्त बनाना जरूरी है. वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने राज्य में मजबूत कार्बन बाजार ढांचा विकसित करने की जरूरत बतायी. कहा कि कार्बन बाजारों और जलवायु वित्त का लाभ उठाकर राज्य वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बैठाते हुए जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है. कार्यशाला में टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के अध्यक्ष डॉ एके रस्तोगी समेत अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किये.